कृषि क्षेत्र में कम विकास होना

7441. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी वर्तमान कानून के कारण कृषि भूमि का समुचित विकास नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गत वर्षों में अनेक मुख्य मंत्रियों ने भी इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूमि-सुधार के संबंध में वर्तमान कानूनों में व्यापक परिवर्तन करने के लिए कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया है;

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) यह एक स्थापित तथ्य है कि कृषि भूमि की उत्पादकता अनुमाप निरपेक्ष होती है और अनेक मामलो में छोटी जोतों में प्रति इकाई पैदावार अधिक होती है, अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान भूमि परिसीमन कानूनों की वजह से कृषि भूमि का विकास कर पाना संभव नहीं है।

(ख) विगत वर्षों में भारत सरकार द्वारा मुख्य मंत्रियों के अनेक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और उनमें से किसी भी सम्मेलन में इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित मुद्दा नहीं उठाया गया।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भूमि सुधारों के लिए वर्तमान कानून में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए कार्रवाई करने का प्रश्न भारत सरकार के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

Implementation of centrally sponsored schemes to boost agricultural production

7442. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of the Centrally Sponsored Schemes implemented in Uttar Pradesh during the last three years with a view to boost agricultural production, particularly in Hill Districts of U.P.;

(b) the achievements made under these schemes during the above period;

(c) the expenditure incurred therein so far;

(d) the incentives being provided to farmers in the State to boost the agricultural/horticultural production; and

(e) the steps proposed to be taken by Government to encourage the farmers of the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) The following important Central/Centrally Sponsored Schemes are being implemented in Uttar Pradesh including the hill districts of U.P. during the last 3 years;

1. National Watershed Development Project for Rainfed Areas.
2. Integrated Programme for Rice Development (IPRD) during 1992-93 & 1993-94 and Integrated Cereal Development Programme in Rice based Cropping System Areas (ICDP-Rice) during 1994-95.
3. Special Foodgrains Production Programme on Wheat (SFPP-Wheat) during 1992-93 and 1993-94 and Integrated Cereal Development Programme in Wheat Based Corpping System Areas (ICDP-Wheat) during 1994-95.
4. Balanced & Integrated Use of Fertilizers.
5. Reclamation of Alkali Soils.
6. Oilseeds Production Programme.
7. National Pulses Development Programme.
8. Development of Commercial Floriculture.
9. Development of Mushrooms.
10. Development of Tropical Arid Temperate Fruits.
11. Development of Vegetables.
12. Use of Plastics in Agriculture.

An amount of about Rs. 154 crores was released to the State Government in respect of these schemes during 1992-93, 1993-94 and 1994-95. In addition, an amount of Rs. 115 crores was released to the State Government during 1992-93 and 1993-94 for concessional sale of decontrolled fertilizers to farmers. The implementation of the schemes has helped in substantial increase in production of foodgrains and oilseeds over the production in 1991-92.

(d) and (e) To boost agricultural/horticultural production in the State, incentives are being provided to resource poor farmers for the use of critical inputs like seeds/planting material, farm implements, seed minikits, etc. Demonstrations and farmers' training are also organised on production technology, Integrated Pest Management, etc. Assistance is also provided to farmers for area expansion and drip installation, mulching and polygreen houses under horticulture programmes. These measures will be continued during the Eighth Plan period.

Uniformity in the Prices of Fruits and Vegetables

7443. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is uniformity in the prices of fruits and vegetables being sold by the outlets of Mother Dairy in Delhi;

(b) if not the reasons therefor; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to remove the difference in prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) The variation is mainly to avoid problems of under-pricing/over-pricing in relation to the open market where the prices vary from lacality to locality.

(c) Not necessary in view of above.

दलहनों के उत्पादन का लक्ष्य

7444. **प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान दलहनों के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शुष्क क्षेत्रों में लघु और सीमान्त कृषकों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई व्यावहारिक योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) वर्ष 1994-95 के लिए दलहनों के लिए निर्धारित लक्ष्य 15.5 मिलियन मीटरी टन था।

(ख) तथा (ग) दलहन मूलतः वर्षा सिंचित फसलें है। इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी राज्यों में 223 जिलों को कवर करते हुए एक केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत, लघु तथा सीमान्त किसानों सहित सभी श्रेणी के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता विभिन्न घटकों जैसे बीजों के उत्पादन और वितरण, उन्नत फार्म उपकरणों, छिड़काव सैटों, एकीकृत कीट प्रबन्धन, दाल प्रोसेसरों, भण्डारण धानियों, सूक्ष्म-पोषकतत्वों, राइजोबियम कल्चर आदि के लिए दी जाती है।

दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

7445. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है देश में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की दर में निरन्तर कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले कुछ दशकों के आंकड़े एकत्र किये हैं तथा दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में निरंतर कमी के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत दशकों में दालों के प्रति हैक्टेयर उत्पादन में कोई संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश दालों के उत्पादन के लिए केवल 30 प्रतिशत परिष्कृत बीज